पूर्ण बजट और अंतरिम बजट : एक प्रश्न

लेखक- शाजी विक्रमण (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

28 जनवरी, 2019

"बजट 2019: अपने कार्यकाल के अंत में, सरकार आम तौर पर पूर्ण बजट के बजाय एक लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) प्रस्तुत करती है। इसमें अंतर क्या है? अंतरिम बजट में कई वर्षों से क्या शामिल किया जाता रहा है या अगली सरकार के लिए इसमें क्या छोड़ दिया जाता है, इस आलेख में हम इस पर एक नजर डालेंगे।"

1 फरवरी को, सरकार चुनावों से पहले अपना आखिरी बजट पेश करने के लिए तैयार है। परंपरागत रूप से, अपने कार्यकाल के अंत में सरकार एक पूर्ण बजट के बजाय एक लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) प्रस्तुत करेगी।

क्या है लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट)?

लेखानुदान को अंतरिम बजट के रूप में भी जाना जाता है, अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि सरकार वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल-मार्च) के लिए खर्च के लिए संसद की मंजूरी चाहती है जिसमें वेतन का भुगतान, विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रम आदि शामिल है। इसके अलावा, जब तक कि एक नई सरकार सत्ता में आ नहीं जाती और एक पूर्ण बजट नहीं पेश करती, तब तक इसमें कराधान संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। इन वर्षों में, कुछ सरकारों ने लेखानुदान में नीतिगत घोषणाएं या कर दरों को कम किया है।

लेखानुदान को क्यों पेश किया जाता हैं?

इस संदर्भ में तर्क यह है कि मंत्रालयों और विभागों के पास विभिन्न अनुदानों के लिए, इन पर बहस करने के साथ-साथ कराधान में परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान के लिए संसद से अनुमोदन प्राप्त करने का समय नहीं रहता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कि यह नई सरकार को अपनी नीति की दिशा में संकेत देने वाला होगा, जो अक्सर बजट में परिलक्षित होता है। इसलिए, 1948 में इसकी शुरुआत में, जहाँ वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी ने एक लेखानुदान प्रस्तुत किया और इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला नियमित बजट पेश किया, ज्यादातर सरकारों ने इस सम्मेलन का अनुसरण किया था।

कई वित्त मंत्रियों, जिनमें दो राष्ट्रपति बने, आर. वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी ने अपने अंतरिम बजट में उल्लेख किया है कि किस तरह से संवैधानिक औचित्य बताते हैं कि नई सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कर और व्यय नीतियों को तैयार करे।

NDA के पिछले वित्त मंत्रियों का अंतरिम बजट पर अनुभव?

यशवंत सिन्हा: उन्होंने दो सरकारों के लिए अंतरिम बजट पेश किया - 1991 में श्री चंद्र शेखर के लिए और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। भारत के सबसे बड़े बैलेंस-ऑफ-पेमेंट संकट की छाया में, सिन्हा को मार्च, 1991 में एक अंतरिम बजट पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कांग्रेस, जिसने चंद्रशेखर सरकार का समर्थन किया था, ने पूर्ण बजट को समर्थन देने से इनकार कर दिया। सिन्हा ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने में लगी हुई है।

"इसके लिए समय चाहिए। इसलिए, मैं मई, 1991 में नियमित बजट 1991-92 तक पेश किए जाने की प्रतीक्षा करने की सदन से विनती करता हूं। ऐसा नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद सरकार ढह गई। अंतरिम बजट में, सिन्हा ने विनिवेश पर देश की पहली नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 1991-92 में 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए म्यूचुअल फंड और वित्तीय और निवेश संस्थानों के पक्ष में चुनिंदा राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों में अपनी इक्विटी का 20% तक विनिवेश करेगी। सिन्हा अब कहते हैं कि यह एक अस्थायी घोषणा थी (जिसे जुलाई, 1991 के बजट में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में आगे बढ़ाया था) और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, जिसके साथ सरकार सहायता के लिए बातचीत कर रही थी। वेंकटरमण ने भी 1980-81 के अपने अंतरिम बजट में सदन से इस बात की प्रतीक्षा की कि देश को फिर से आगे बढ़ाने के उपायों को अपनाने के लिए एक नियमित बजट का इंतजार किया जाए क्योंकि अनुमानों पर काम करने और बजट को पेश करने का समय नहीं था।

जसवंत सिंह: वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अंतिम वर्ष में, तीन से अधिक सुस्त वर्षों और अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर होने के बाद, 3 फरवरी, 2004 के अंतरिम बजट में सिंह ने स्टैंप ड्यूटी संरचना, चाय के लिए पुनर्जीवित पैकेजों में बदलाव की घोषणा की और चीनी उद्योग और मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते का विलय किया। अंतरिम बजट में कहा गया है, जबकि आयकर अधिनियम में बदलाव वर्तमान में प्रस्तावित नहीं किए जा रहे हैं, यह सरकार की और हमारी भी प्रतिबद्धता है कि बिजली क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध राजकोषीय लाभ को 2012 तक बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके बाद सूचीबद्ध फर्मों में निवेश के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के रूप में कर लाभ, स्थिरता प्रदान करने के लिए आगे तीन साल के लिए बढ़ाया गया था। 25,000 रुपये का सामान भत्ता जो कि विदेश जाने वाले और लौटने वाले भारतीयों को दिया जाता है, को पहले उस अंतरिम बजट में उठाया गया था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों में बड़े बदलावों की घोषणा और एक मिनी-बजट को प्रस्तुत करने के कारण सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। गैर-कृषि सामानों पर सीमा शुल्क की चरम दर 25% से घटाकर 20% कर दी गई थी, 4% समाप्त किए गए सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क और परियोजना आयात, कोयला और बिजली क्षेत्र पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया था।

यूपीए दृष्टिकोण क्या था?

प्रणब मुखर्जी: उन्होंने यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के अंत में 2008-09 में अंतरिम बजट पेश किया था। यह स्वीकार करते हुए कि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और संवैधानिक औचित्य का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि असाधारण आर्थिक परिस्थितियों ने असाधारण उपायों का विलय किया है। अब इस तरह के उपायों पर कार्य करने का समय है, उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों को आसान बनाने की घोषणा काफी मद्दगार साबित होगी।

जब राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बजट के 2.5% से 6% तक बेहद संशोधित किया गया था - मुखर्जी द्वारा जनवरी में कर कटौती के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये एकत्र करने के बाद एक प्रमुख राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा की गई थी। कई अर्थशास्त्री और कुछ मंत्री अभी भी इसे राजकोषीय सुधार में गिरावट के लिए मुख्य कारक मानते हैं।

पी. चिदंबरम: ये मुखर्जी के राष्ट्रपति भवन चले जाने के बाद वित्त मंत्रालय में वापस आये, चिदंबरम ने 17 फरवरी, 2014 को अंतरिम बजट की अपनी प्रस्तुति शुरू की। "उन्होंने कहा कि सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कर कानूनों में बदलाव के संबंध में कोई घोषणा करने का प्रस्ताव नहीं दिया है। इसके बाद: "हालांकि, वर्तमान स्थिति कुछ हस्तक्षेपों की मांग करती है जो नियमित बजट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। विशेष रूप से, विनिर्माण क्षेत्र को तत्काल बढ़ावा देने की जरूरत है। "चिदंबरम ने कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटाने के साथ पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-ड्यूरेबल्स में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष कर में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया।

क्या विपक्ष आमतौर पर अंतरिम बजट में प्रावधानों को चुनौती देता है?

2014 का यह अंतरिम बजट राजनीतिक रूप से सुस्त हो गया, जसवंत सिंह ने इसे अंतरिम बजट के बजाय चुनावी बजट कहा। सिंह ने कहा, अंतरिम बजट का सिद्धांत या तो चुनाव के बाद की उत्तराधिकारी सरकार के लिए नीतिगत घोषणाओं से जुड़ता है या केवल चर्चा और परामर्श के माध्यम से ऐसा करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अंतरिम बजट "क्षय और नीतिगत पक्षाघात के दशक के बाद यूपीए का अंतिम खराब कार्य था।" जवाब में, चिदंबरम ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा: मैं इस बहस के स्तर को 8वीं कक्षा के बच्चे के बहस के स्तर तक नहीं ले जाना चाहता हूँ।

उन्होंने बीबीसी को बताया कि जो वह (मोदी) अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं उसे डाक टिकट के पीछे लिखा जा सकता है। मई 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के बाद मोदी ने वापसी की। जब यूपीए के एक शीर्ष आर्थिक सलाहकार ने शिष्टाचार भेंट की, तो मोदी ने स्पष्ट रूप से उनसे पूछा कि जब यूपीए के पास मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इतने सारे अर्थशास्त्रियों का हुजूम था तो फिर अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई थी?

क्या कोई संकेत है कि आगामी बजट कैसा होगा?

1 फरवरी तक चलने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% कोटा जैसे फैसलों की घोषणा के साथ, सरकार अच्छी तरह से खराब हो चुकी नीति को छिपा सकती है। यह देखा जाना बाकी है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं, या वह उन संकेतों का खुलासा या नीतिगत दिशाओं के बारे में क्या उपाय करते हैं।

जीएसटी लागू होने के साथ, वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने के निर्णय अब जीएसटी परिषद के पास हैं। करों के बढ़ते विचलन या आय के साथ, कार्रवाई राज्यों में बहुत अधिक स्थानांतरित हो गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बड़े स्तर पर एकीकरण का मतलब यह भी है कि चीन में विकास पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास की धीमी गति होगी। मुद्दा यह है कि क्या बजट को बहुत अधिक महत्व दिया जायेगा और क्या घोषित किए गए किसी भी नीतिगत बदलाव को एक अन्य सरकार, जो अलग राजनीतिक और आर्थिक दर्शन में विश्वास रखते है, द्वारा समर्थन दिया जायेगा।

GS World टीम...

अंतरिम बजट और आम बजट

चर्चा में क्यों?

- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह अब 1 फरवरी को रेल मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे।
- अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण गोयल को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- इस बार आम बजट की जगह अंतरिम बजट पेश होगा।
- परंपरा के अनुसार जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं, केंद्र सरकार पूरे वित्त वर्ष की बजाय कुछ महीनों तक के लिए ही बजट पेश करती है और चुनाव होने के बाद नई गठित सरकार पूर्ण बजट पेश करती है।

क्या है अंतरिम बजट?

- अंतरिम बजट को हम वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान मांग और मिनी बजट के नामों से भी जानते हैं।
- जब केंद्र सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने के लिए समय नहीं होता है तो वह अंतरिम बजट पेश करती है।
- लोकसभा चुनाव के समय सरकार के पास वक्त तो होता है लेकिन परंपरा के मुताबिक चुनाव पूरा होने तक के समय के लिए बजट पेश करती है।
- यह पूरे साल की बजाय कुछ महीनों तक के लिए ही होता है। हालांकि, अंतरिम बजट ही पेश करने की बाध्यता नहीं होती है लेकिन परंपरा के मुताबिक इसे अगली सरकार पर छोड़ दिया जाता है।
- नई सरकार बनने के बाद वह आम बजट पेश करती है।

अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है?

- मौजूदा सरकार उस परिस्थिति में अंतरिम बजट पेश करती है जब उसके पास पूर्ण बजट पेश करने का पर्याप्त वक्त नहीं होता या लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक होता है।
- लोकसभा चुनाव के नजदीक होने की स्थिति में पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी आने वाली नई सरकार पर होती है।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर. के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को पेश किया था।
- आर. के. षणमुखम चेट्टी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्तमंत्री थे। हालांकि ये पूर्ण रूप से बजट नहीं था, बल्कि देश की आर्थिक नीति और अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी।

- इस बजट में ना तो कोई नए नियम लागू किए गए और ना ही कोई नई टैक्स प्रणाली लागू की गई, क्योंकि साल 1948-1949 के बजट में केवल 95 दिन ही बचे हुए थे।

क्या है आम बजट?

- संविधान में 'बजट' शब्द का जिक्र नहीं है जिसे बोलचाल की भाषा में आम बजट कहा जाता है उसे संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण (एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट) कहा गया है।
- फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का उस साल के लिए सरकार का विस्तृत ब्योरा होता है। आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है।
- बड़े तौर पर इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्योरा पेश किया जाता है।

लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) क्या है?

- लेखानुदान के तहत सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करती है।
- इसके पीछे सैद्धांतिक तर्क यह है कि चूंकि चुनाव के बाद दूसरे दल या गठबंधन की सरकार बन सकती है, ऐसे में मौजूदा सरकार पूरे साल के लिए नीतिगत फैसले नहीं ले सकती।
- हालांकि, इस पर नियम स्पष्ट नहीं हैं और ये बाध्यकारी भी नहीं है।

अंतरिम बजट और आम बजट में अंतर

- दोनों ही बजट में सरकारी खर्चों के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है लेकिन अंतरिम बजट आम बजट से अलग हो जाता है।
- अंतरिम बजट में सामान्यत: सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करती। हालांकि, इसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है। चुनाव के बाद गठित सरकार ही अपनी नीतियों के मुताबिक फैसले लेती है और योजनाओं की घोषणा करती है।
- हालांकि, कुछ वित्त मंत्री पूर्व टैक्स की दरों में कटौती जैसे नीतिगत फैसले ले चुके हैं। इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली के अंतरिम बजट से भी ऐसी ही उम्मीदें की जा रही हैं कि इनकम क्लास को टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है।

अंतरिम बजट और लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) में अंतर

- जब केंद्र सरकार पूरे साल की बजाय कुछ ही महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्च के लिए अनुमति मांगती है तो वह अंतरिम बजट की बजाय वोट ऑन अकाउंट पेश कर सकती है।
- अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं लेकिन दोनों के पेश करने के तरीके में अंतर होता है।
- अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतरिम बजट में केन्द्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है।
2. लेखानुदान में केन्द्र सरकार केवल खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतरिम बजट को, मिनी बजट भी कहा जाता है।
2. संविधान के अनुच्छेद-112 में 'बजट' शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे बोलचाल की भाषा में आम बजट कहते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. In interim budget, the central government gives the account of revenue along with expences.
2. In vote on account, the central government asks for the approval of only expenses from the parliament.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements-

1. Interim budget is also called mini budget.
2. Word 'Budget' is mentioned under the article-112 of the Constitution which is colloquially called general budget.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र:- पूर्ण बजट और अंतरिम बजट को स्पष्ट करते हुए अंतरिम बजट के सम्पूर्ण प्रक्रिया को समझाइये। (250 शब्द)

Q. Elucidating full budget and interim budget, explain the important process of interim budget. (250 Words)

नोट : 25 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2 (c) होगा।